



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 2012/आश्विन 13, 1934

No. 228]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 2012/ASVINA 13, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2012

जांच शुरुआत (निर्णायक समीक्षा)

विषय : ताईवान, चीन-जनवादी गणराज्य, इण्डोनेशिया, जापान, कोरिया आर.पी., मलेशिया, थाईलैण्ड और यूएसए के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पालीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) सस्पेंशन ग्रेड रेजिन के आयातों के संबंध में संबंधित पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

सं. 21/29/2011-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमा शुल्क-टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसार ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, इण्डोनेशिया, जापान, कोरिया आर.पी., मलेशिया, थाईलैण्ड और यूएसए (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पालीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) सस्पेंशन ग्रेड रेजिन (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. 14/08/2006-डीजीएडी के तहत प्रकाशित की गई थी। इस निष्कर्ष के आधार पर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क 23 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 11/2008-सीमा शुल्क के तहत राजस्व विभाग ने अधिरोपित किया था।

यतः, मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (डीसीडब्ल्यू), केम्प्लास्ट सन्मार लिमिटेड (केम्प्लास्ट), रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और डीसीएम श्रीराम कन्सालीडेटेड लिमिटेड (डीसीएम) (जिन्हें एतदपश्चात् याचिकाकर्ता कहा गया है) ने अधिनियम एवं नियमों के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की ओर से प्राधिकारी के समक्ष विधिवत प्रमाणयुक्त आवेदन-पत्र संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को उसकी परिणामी क्षति होने का आरोप लगाते हुए दायर किया है और संबद्ध देश के मूल अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित

पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी निरंतरता बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

1. वर्तमान समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद विनायल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालीमर (सस्पेंशन ग्रेड) है, जहाँ विभिन्न पालीमर चैनस एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं। पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में, ज्ञात यह उत्पाद सीमा शुल्क वर्गीकरण सं. 3904 के अंतर्गत आता है। यह विचाराधीन उत्पाद स्पेशलिटी पीवीसी सस्पेंशन रेजिन्स जैसे 'क्रासलिन्कड पीवीसी', क्लोरीनेटिड पीवीसी (सीपीवीसी), विनायल क्लोराइड-विनायल एसीटेट कोपोलीमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेजिन और पीवीसी क्लेण्डिंग रेजिन का अपवर्जन करता है। विचाराधीन उत्पाद को "पालीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) रेजिन सस्पेंशन ग्रेड" या "पीवीसी सस्पेंशन रेजिन" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है।

2. चूँकि वर्तमान जाँच इस समय प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जाँच है, इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही होगा जो मूल जाँच में था।

3. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है और इनके आयात को 3904 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत, क्लीयर किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह इस जाँच के दायरे के अंतर्गत किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

4. यह याचिका डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (डीसीडब्ल्यू), चेम्प्लास्ट सन्मार लिमिटेड (चेम्प्लास्ट), रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रिलायन्स) तथा डीसीएम श्रीराम कन्सालीडेटेड लिमिटेड (डीसीएम) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। मैसर्स फिनोलेक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जो संबद्ध वस्तु का भारत में अन्य ज्ञात एकमात्र उत्पादक है, ने इस याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि डीसीएम श्रीराम कन्सालीडेटेड लिमिटेड को छोड़कर किसी भी अन्य याचिकाकर्ता कम्पनी ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता कंपनी, जो संबद्ध वस्तु का आयात करती है, पाटन का लाभ उठाने के उद्देश्य से आयात नहीं करती है। इन याचिकाकर्ता कम्पनियों का थ्रस्ट आयातों की ओर नहीं है। कम्पनी का थ्रस्ट अपना उत्पाद ही है।

5. प्राधिकारी ने मामले की जांच की और पाया कि याचिकाकर्ता कंपनियों में से कोई भी कंपनी समरूप व्यापारी नहीं है और उन्होंने पाटन से लाभ उठाने के लिए आयात नहीं किया है।

याचिकाकर्ता का मुख्य ध्यान उत्पादक और संबद्ध वस्तु के उत्पादक का बना रहा। प्राधिकारी ने विचार किया है कि कोई भी याचिकाकर्ता कम्पनी नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का आयातक नहीं है। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी की जाँच करने के पश्चात् यह निश्चय किया है कि याचिकाकर्ता कम्पनियाँ नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और यह याचिका नियम 5 के अंतर्गत बने नियमों में दी गई स्थिति की प्रक्रिया को संतुष्ट करती है।

समान वस्तु

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबंधित देश से आयातित उत्पाद के भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य तथा उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन और टैरिफ वर्गीकरणों के रूप में समान है। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा उपभोक्ता इनका अंतर्बदल का प्रयोग कर सकते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को इस समीक्षा जांच के उद्देश्य के लिए संबंधित देशों से आयातित वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना गया है।

संबद्ध देश

7. वर्तमान आवेदन ताईवान, चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आर पी, मलेशिया, थाईलैंड और यू एस ए (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन के आरोप के बारे में दायर किया गया है।

सामान्य मूल्य

8. याचिकाकर्ताओं ने ताईवान, कोरिया आर पी, यूएसए, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए हरीमन केम्सल्ट रिपोर्ट में उद्धृत कीमतों का उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता ने माह-वार सामान्य मूल्य का निर्धारण रिपोर्ट में दी गई औसत उच्चतम और न्यूनतम कीमत पर विचार करते हुए किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने विदेशी उत्पादकों की कीमतों का निर्धारण किया है और पाया है कि बिक्री कीमतें प्रस्तावित जांच अवधि के कुछ महीने में उत्पादन लागत से कम हैं। जहां बिक्री कीमतों को सामान्य मूल्य के रूप में माना है। वहां उन्होंने दावा किया है कि चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाए और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 (7) में दी गई शर्तों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए, जिसमें गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के विधिवत समायोजन के आधार पर किया है। प्राधिकारी ने, जांच के

उपरांत, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार किया है।

निर्यात कीमत

9. निर्यात कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सूचना सेवा (आई बी आई एस) द्वारा प्रदान कराए गए संबद्ध देशों से सौदावार, आयात आंकड़ों पर आधारित भारित औसत कीमत के रूप में किया गया था। इस कीमत समायोजन का दावा समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और कमीशन के आधार पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए किया गया था। समयावधि के साथ कीमतों में भारी भिन्नता को देखते हुए याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित जांच अवधि के प्रत्येक माह के लिए पृथक निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

पाटन मार्जिन

10. समयावधि के अंदर भारी कीमत भिन्नता के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने जांच अवधि के प्रत्येक माह के लिए पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है।

11. याचिकाकर्ताओं ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य निर्यात कीमत की तुलना में अत्यधिक उच्च है, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहा, जो समीक्षा जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराता है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को विपरीत कीमत प्रभाव के रूप में वास्तविक क्षति हुई है जो कीमत में कटौती कीमत हास और लाभदायकता, लगाई गई पूंजी पर आय और घरेलू उद्योग के नकदी लाभ में कमी से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण सतत भौतिक क्षति हुई है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सतत क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है जो समीक्षा जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते हैं।

पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

13. उपर्युक्त जानकारी और दायर किए गए प्रामाणिक आवेदन के मद्देनजर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी

संबद्ध वस्तु के संबंध में प्रभावी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क के समापन से पाटन की अवस्थिति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हैं।

जांच अवधि

14. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 (12 माह) है। तथापि क्षति विश्लेषण के लिए 1 अप्रैल, 2008 से जांच की अवधि की समाप्ति तक का समय अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 और जांचावधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

15. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में मूल जांच के दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 को अधिसूचना संख्या 14/8/2006-डीजीएडी के तहत प्रकाशित अंतिम निष्कर्ष के सभी पहलू शामिल होंगे।

16. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के तथा उसके अधीन बने नियमों के सभी प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए, भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

भारत सरकार
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा नं. 243, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है।

समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं जारी रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ इस जांच के शुरू होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक सूची पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक सूची पृष्ठ सं. इत्यादि सहित)। प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिह्नित होना अनिवार्य है।

22. किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को आगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की दो-दो प्रतियाँ आवश्यक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया हो; उस सूचना के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ समुचित कारणों सहित इस आशय का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है तथा/अथवा ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए या रिक्त छोड़ दिया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

25. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच पर गोपनीयता हेतु निवेदन को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु निवेदन प्राधिकृत नहीं है अथवा सूचना प्रदायक या तो सूचना सार्वजनिक करने को अनिच्छुक है या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत नहीं कर रहा है, तो वे इस तरह की सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय रूपान्तर के बिना अथवा गोपनीयता की माँग के लिए उचित कारण का ब्यौरा दिए बिना किसी तरह का निवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा इसे स्वीकार करते हुए, इस तरह की सूचना प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उसे किसी अन्य पार्टी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपान्तर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2012

Initiation (Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping duty on imports of Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Grade Resin originating in or exported from Taiwan, People's Republic of China, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and USA.

No. 21/29/2011-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Grade Resin (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Taiwan, People's Republic of China, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and USA (hereinafter referred to as the subject countries). The final findings notification of the Authority was published vide notification No. 14/8/2006-DGAD dated 26th December 2007. On the basis of the findings, anti dumping duties on the subject goods imported from the subject countries were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 11/2008-Customs dated 23rd January, 2008.

WHEREAS, M/s DCW Limited (DCW), Chemplast Sanmar Limited (Chemplast), Reliance Industries Ltd (RIL) and DCM Shriram Consolidated Ltd. (DCM) (hereinafter referred to as the petitioners), have filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Product under Consideration

1. Product under consideration in the present review investigation is homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade), where various polymer chains are not linked to each other, falling under customs classification no. 3904, known as PVC suspension resin. The product under consideration excludes specialty PVC suspension resins such as cross-linked PVC, chlorinated PVC (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAc), PVC paste resin and PVC blending resin. The product under consideration has been referred to as "Poly Vinyl Chloride (PVC) Resin Suspension Grade" or "PVC Suspension Resin" or "the subject goods").
2. Since the current investigation is a Sunset Review investigation into anti-dumping duties currently in force, the scope of the product under consideration is the same as that in the original investigation.
3. The petitioners have submitted that the product under consideration does not have dedicated HS Code and the imports are cleared under different HS Codes falling under 3904. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation and proposed measures.

Domestic Industry & Standing

4. The petition has been jointly filed by DCW Limited (DCW), Chemplast Sanmar Limited (Chemplast), Reliance Industries Ltd (Reliance) and DCM Shriram Consolidated Ltd. (DCM). Finolex Industries Limited, the sole other known producer of the subject product in India has supported the petition. The petitioners have stated that none of the petitioner companies except DCM Shriram Consolidated Ltd have imported the product under consideration during period of investigation. Further they submitted that petitioner company who is importing the subject goods is not resorting to imports in order to benefit from dumping. Thrust of this petitioner company has not turned to imports. The company's thrust continues to be on own production.
5. The Authority has examined the matter and holds that none of the Petitioner companies are a trader per se and have not resorted to imports in order to take advantage of dumping. The focus of the petitioner companies continues to be that of a producer of the subject goods. The Authority after examining the information on record has determined that the petitioner companies constitute domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Like Articles

6. The petitioners have claimed that the product produced by them is a like article to the product imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers use the two interchangeably. Subject goods

3802 GE/12-3

produced by the petitioners are being treated as 'like article' to the goods being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

Subject Countries

7. The present application has been filed in respect of alleged continued dumping of the product under consideration from Taiwan, People's Republic of China, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and USA (hereinafter referred to as subject countries).

Normal value

8. The petitioners for the purpose of determining normal value of product under consideration in Taiwan, Korea RP, USA, Malaysia, Japan, Indonesia and Thailand, have referred to the prices quoted in the Harriman Chemsult report. The petitioners have determined month-wise normal value by considering the average of the highest and the lowest price given in the report. Additionally, the petitioners have determined cost of production of the foreign producers and found that the selling prices were below the cost of production in some of the months of the proposed POI. Wherever selling prices were above cost of production, the petitioners had adopted selling price as normal value. They have claimed that China should be treated as a non-market economy country and the normal value should be determined in terms of Annexure I (7) of the AD Rules, which provides for determination of normal value in a non-market economy. Petitioners have determined Normal Value in China on the basis of cost of production in India; duly adjusted. The Authority, after examination, has considered the normal value of subject goods in subject countries as made available by the applicant.

Export Price

9. The export price has been determined as the weighted average import price from subject countries based on the transaction wise import data provided by the International Business Information Services (IBIS). Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, bank charges and commission to arrive at the net export price. In view of significant variation in the prices with time period, the petitioners have determined separate export price for each of the months of the proposed investigation period.

Dumping Margin

10. In view of the significant variation in the prices over the time period, the petitioners have determined separate dumping margin for each month of the investigation period.
11. Petitioners have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie,

indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries continue to be dumped, to justify initiation of a review investigation.

Injury and Causal Link

12. The petitioners have claimed that domestic industry continues to suffer material injury by way of adverse price effects as evidenced by price undercutting and price suppression leading to deterioration in profits to negative levels, decline in return on capital employed and cash profits, etc. The petitioners have claimed that the continued material injury has been caused due to the dumped imports from the subject countries. The Authority considers that there is sufficient prima facie evidence of continued injury caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries to justify initiation of a review investigation.

Initiation of Sunset Review of Anti Dumping Duty

13. In view of the above information and the duly substantiated application filed, and in accordance with Section 9 A (5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset Review investigation to review the need for continued imposition and enhancement of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

14. The Period of Investigation for the purpose of the present review investigation is 1st April 2011 to 31st March 2012 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 1st April 2008 to the end of the POI, that is, 2008-09, 2009-10, 2010-11 and POI.

Procedure

15. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No.14/8/2006-DGAD dated 26th December 2007.
16. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

17. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

3802 GE/12-4

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.243, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit:

19. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this review investigation.

Submission of information on confidential basis.

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
22. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a

statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority